MR. CHAIRMAN: Next Special Mention. Shri Thangabaalu. Not here. Next special Mention. Shri S. P. Malaviya.

Reference to the Reported closure of clothes Mills at Modi Nagar.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : (उत्तर प्रदेश): सभापति जी, दिल्ली से मिला हुआ उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजियाबाद और वहां एक औद्योगिक नगर है मोदी नगर, जहां कि पांच कपड़ा-मिले बंद हो गई हैं और उसके कारण करीब-करीब 10 हजार मजदूर बेरोजगार हो गये हैं। इसके अतिरिक्त अगर यह मान लिया जाए कि एक मजदूर के परिवार में चार लोग हैं तो करीब-करीब 40 हजार व्यक्ति आज वहां पर भुखमरी के कगार पर हैं। 12 मई को इस तालाबंदी के विरोध में गाजियाबाद में पूर्णरूप से हड़ताल रही करीब-करीब वहां पर जितने मजदूर संगठन हैं वे सब मांग कर रहे हैं कि सभी मिलों को खोला जाए और मजदूरों की बेरोजगारी को खत्म किया जाए। लेकिन वहां पर हिंसा का वातावरण हैं। जुलाई 1983 में एक दर्जन मजदूर वहां पर मौत के शिकार हुए। इसके अतिरिक्त करीब 50 से अधिक मजदूर मारे जा चुके हैं। और पांच सौ से अधिक मजदूर वहां पर हिंसा में घायल हो चुके हैं? तीन साल पहले वहां पर कपड़ा यूनियम के अध्यक्ष श्री जयप्रकाश की हत्या हुई थी। आज से चार दिन पहले 11 मई को मजदूर नेता श्री इन्द्र पाल पर प्राणघातक हमला हुआ और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। वहां की पुलिस मिल-मालिकों से मिली हुई हैं। वह हस्तक्षेप नहीं करती है और इस कारण से स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे तुरन्त हस्तक्षेप करे जिससे मजदूरों की हत्या बन्द हो और जो मजदूर बेरोजगार हो गए हैं उनकी बेरोजगारी समाप्त हो और मजदूरों के परिवार जो भुखमरी के कगार पर हैं उनको रोटी मिल सके।

REFERENCE TO THE REPORTED RESENTMENT AMONGST WORKERS OF THE PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS OVER INTERIM RELIEF

[उपसभापति डा० (श्रीमती) **नाजमा हेपतुल्ला** पीठासीन हुई]

श्री लक्ष्मी नारायण (दिल्ली) : उपसभापति महोदया, जितनी पब्लिक अन्डरटेकिंस हैं उन सब के कर्मचारियों को हमारे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन दिया जाता है। परन्तु बड़े खेद की बात है है कि जब अब चौथे आयोग ने अंतरिम सहायता का एलान किया तो उनको इससे वंचित रखा गया। मंहगाई भत्ते के लिये उन्हें बाध्य किया जाता है और उनसे कहा जाता है कि इंडस्ट्रीयल डी० ए० की तरफ स्विच-ओवर करें। जब वे लोग इंडिपेन्डेन्ट पे स्केल की लड़ाई करते हैं तो भारत सरकार को उनको मना करती है। उन्होंने माननीय वित्त मंत्री जी के निवास स्थान पर 7 मई को धरना भी दिया। यह धरना थोड़े समय के के लिये दिया गया। उसके बाद वे लोग उनसे मिले। लेकिन मिलने के बाद भी कोई मसला हल नहीं हुआ। चूंकि माननीय वित्त मंत्री जी अभी यहां पर विराजमान हैं, मैं उनके निवेदन करना चाहता हुं कि भारत सरकार इस मामले में अपनी नीति स्पष्ट करे। जान-बूझकर आन्दोलन को दावत देना, मैं समझता हूं, अच्छा बाकी नहीं है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि जितने भी सार्वजनिक संस्थान है, पब्लिक अन्डण्रटेकिंग हैं उन सब के कर्मचारियों को अलग से पे स्केल बना कर दें और भारत सरकार उनको ज्यादा दे या कम दे, यह तो उन लोगों की अपनी हिम्मत है, लड़कर जितना ले सकते हैं, लें। लेकिन जब यह बात करते हैं कि उनको भी सरकारी कर्मचारियों के अनुसार वेतन आयोग के दिये हुए वेतनमान मिलेंगें तो सरकारी कर्मचारियों को जो अन्य सुविधाएं दी जाती हैं उनसे उन्हें

क्यों वंचित रखा जता है ? उन्हें अन्तरिम सहायता दी जाये, डियरनेस एलाउन्स जो सरकारी कर्मचारियों को मिलता है वह दिया जाये । उन्हें इंडस्ट्रियल डी०ए० के लिये बाध्य नहीं किया जाना चाहिए । मैं समझता हूं कि सरकार इस पर विचार करेगी और इस तरीके से आज जो डिसक्रिमिनेशन किया जा रहा है उसको समाप्त करने पर विचार करेगी ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Sukomal Sen.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE (West Bengal): He has gone Io the hospital.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Why?

THE NIRMAL CHATTERJEE: He was slightly sick this morning.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now. Shri Madhavrao Scindia to make a statement.

STATEMENT BY MINISTER

Freight rate for salt for Human consumption

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): Madm, Members may recall the general discussion on Railway Budget which took place in March 1985 and the reply thereto on 21st March, 1985. The revised fare and freight rates have accordingly taken effct from 15-4-85. However, some of the Hon'ble Members had made mention about giving some relief in the matter of freight rates for salt for human consumption. We have been giving considerable iaht to this matter. In deference to the wishes of the Hon'ble Members and on grounds of sentiment, i; has been decided to exempt salt for human consumption from the levy of the 10 per cent supplementary charge on consignments moving over 500 Kms. I, therefore, announce that the 10 per cent supplementary charge imposed on goods traffic with effect from 15-4-1985 will not be leviable on salt for human consumption with effect from 1-6-1985.

THE FINANCE B|LI* 1985-*ontd.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Further discussion on the Finance Bill— Shri Nirmal Chatterjee. You have got 26 minutes. I do not want to disturb you. You try to frame your speech within that time limit.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE (West Bengal)) Thank you, Madam, for your consideration. I may mention incidentally that I had an agreement with the previous Deputy Chairman that as soon as he rang the bell I would stop and so long as I continued to speak he would not ring the bell.

THE DEPUTY CHAIRMAN: That agreement has to be renewed again.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: Madam, I was referring to the dwindling importance of the Finance Bill. In fact, Madam, as has been mentioned at page 48 of Part 'B' of the Finance Minister's speech, the net reduction in deficit of the Union Budget would be only to the extent of Rs. 311 crores and another Rs. 132 crores of course would be added to the States during 1985-86. I am not talking of the deficit. The reduction on the basis of the efforts of the Finance Bill would be to the extent of this amount only. That indicates the dwindling significance in teems